एक्ज़िम बैंक EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस

निर्यात लाभ

मार्च 2018
खंड XXXIV अंक I

इस अंक में

1-3 लचीली व्यापार वित्त व्यवस्था का निर्माण
4 राज्यावलोकन: मध्य प्रदेश
5 उत्तर प्रदेश: निर्यात संभाव्यता का लाभ उठाना
6 विशेष कवरेज: 13 वां सीआईआई-एक्ज़िम बैंक भारत-अफ्रीका भागीदारी सम्मेलन
7 विशेष कवरेज: एडफिएप वार्षिक बैठक 2018
8 आर्थिक सर्वे 2017-18: संक्षिप्त विवरण
9 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
10 तिमाही गतिविधियां
11 विशेष रिपोर्ट: भारत-एस्टोनिया व्यापार संबंध
12 एक्ज़िम बैंक गतिविधियां
13 देशों का सूक्ष्मावलोकन
14 मुद्रा की प्रवृत्तियां
15 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य
16 व्यापार और भागीदारी अवसर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

मुख्य कार्यालय :
केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400 005
Tel.: 022 2217 2600
Email : ccg@eximbankindia.in

लचीली व्यापार वित्त व्यवस्था का निर्माण

वित्तीय संकट ने सभी देशों की वित्तीय व्यवस्था में मौजूद कमियों को उजागर किया है। इसकी बहुस्तरीय समस्याओं के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो विकृत क्रेडिट दशाओं के साथ प्रमुख ट्रांसमिशन चैनल के रूप में भी उभरा। वस्तुतः व्यापार वित्त में आई यह गिरावट जिसने उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक प्रभावित किया, उन पर अब तक हावी है। व्यापार वित्त में उत्पन्न यह समस्या केवल वित्तीय संकट के कारण ही नहीं, बल्कि वित्तीय संकट के समय उत्पन्न प्रतिक्रिया से भी उभरी है, विशेषकर सामान्य विनियामकों द्वारा कड़े नियम अपनाए जाने के कारण।

वित्तीय संकट के बाद से वित्तीय विनियामकों में अभूतपूर्व मजबूती देखी गई, लेकिन जिन अत्यावश्यक परिणामों की अपेक्षा थी, वे उससे प्राप्त नहीं हुए। पूँजीगत प्रभार के पुनर्मूल्यांकन ने कम जोखिमवाले व्यापार वित्त उत्पादों को अधिक जटिल वित्तीय उत्पादों के समान बना दिया। इस तरह के नियामकीय उपाय के कारण बैंक-मध्यवर्ती व्यापार वित्त प्रभावित हुआ, परिणामस्वरूप वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास भी प्रभावित हुआ।

गहन रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्थाओं में, इस तरह की आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का समाधान केवल पारस्परिक सहयोग द्वारा ही किया जा सकता है। विकासशील देशों के बीच बहुपक्षीय पारस्परिक विचार-विमर्श में व्यापार की भूमिका, दक्षिण-दक्षिण व्यापार संबंधों में व्यापार वित्त की भूमिका विकासशील देशों को प्रभावी व्यापार वित्तपोषण ढांचे के विकास के लिए सामूहिक, समेकित और सुसंगत पहलों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।

विकास वित्त संस्थानों के बीच सहयोग

इस समय उन संरचनात्मक और विकासात्मक चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो व्यापार वित्त की वृद्धि में बाधा डालने के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी नुकसान पहुचा रही हैं। विद्यमान व्यापार सुविधा को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे पहले विकास वित्त संस्थाओं के प्रयासों को समन्वित करना होगा। विकास वित्त संस्थाओं में इंटरनेशनल फाइनैन्शियल कॉर्पोरेशन (आईएफसी), एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, निर्यात ऋण एजेंसियाँ इत्यादि के अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) शामिल हैं।

बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थाओं (एम डी बी) और निर्यात वित्त संस्थाओं (ईसीए) की भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण रही है कि व्यापार-वित्तपोषण में आई कमी का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा न पड़े। इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स 2016 द्वारा व्यापार वित्त पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 75% प्रतिक्रिया देने वालों ने बताया कि एमडीबी तथा ईसीए व्यापार वित्त अंतराल को कम करने में मदद करते हैं। भविष्य में, वैकल्पिक स्थानीय वित्तपोषण क्षमताओं को बढ़ाए जाने तक इन संस्थाओं की भूमिका व्यापार वित्त लेनदेन को सहयोग में महत्वपूर्ण रहेगी।

एमडीबी, ईसीए तथा राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थाएं आपस में संगठित होकर इन्फ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही व्यापार वित्तपोषण क्षमताओं में काफी हद तक वृद्धि कर सकती हैं। एमडीबी, ईसीए और राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थाओं द्वारा इस तरह के लेनदेन में काफी वृद्धि हुई है। जाम्बिया में इतेज़ी - तेज़ी जल विद्युत परियोजना का वित्तपोषण, इस तरह के सहयोग का एक उदाहरण है। इस परियोजना को कई ऋणदाताओं

द्वारा सह-वित्तपोषित किया गया था जिनमें बहुपक्षीय बैंक जैसे - एएफडीबी और यूरोपीय निवेश बैंक; विकास वित्तीय संस्थाएं जैसे - द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका, डच डेवलपमेंट बैंक एफएमओ और फ्रेंच डेवलपमेंट वित्तीय संस्थान PROPARCO तथा निर्यात ऋण एजेंसिया यथा- भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम इंडिया) शामिल हैं।

ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां सह-वित्तपोषण के कारण निर्यात ऋण एजेंसियां बड़ी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने तथा देशी कंपनियों का समर्थन करने में सक्षम रहीं, जो इसके अभाव में संभव नहीं था। उदाहरणार्थ, पर्याप्त निधि के अभाव में, हंगरी निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम हंगरी) हंगरी की कई कंपनियों के बड़े लेनदेन को अपने दम पर सहयोग नहीं दे सका। तथापि, एक्ज़िम हंगरी के सहयोगी दृष्टिकोण ने देशी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान किए। एक्ज़िम हंगरी ने जनरल इलेक्ट्रिक, इंडोनेशियन पावर यूटिलिटी 'पेरुसाहन लिस्टिक नेगारा' तथा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा (ईडीसी) के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना ने न केवल हंगरी से 276 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक का निर्यात सुनिश्चित किया, बल्कि लगभग 4 मिलियन इंडोनेशियाई घरों में बिजली पहुंचाने का भी काम किया। यह स्पष्ट है कि छोटे ईसीए अन्य ईसीए, डीएफआई और एमडीबी के साथ समन्वय कर काफी लाभ उठा सकते हैं। ईसीए और एमडीबी के बीच सहयोग के पर्याप्त उदाहरण भी हैं। ऋण एक्सपोजर के बीमा और गारंटी एक्सपोजर के पुनर्वितरण जैसे सहयोग के उदाहरण पहले से ही मौजूद हैं। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (मीगा) ईसीए तथा राजनीतिक जोखिम बीमा कंपनियों के साथ अपने कुल एक्सपोजर के लगभग 40 प्रतिशत का पुन: बीमा करती है। एक अनुमान के अनुसार अगर प्रमुख एमडीबी मीगा का अनुकरण करते हैं, तो विकास के लिए 169 बिलियन यूएस डॉलर का अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराया जा सकता है।

इसके अलावा ईसीए, एमडीबी और राष्ट्रीय डीएफआई जानकारी साझा करके और वित्तपोषण के लिए एक सक्षम परिवेश के निर्माण के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। सभी संस्थानों को परियोजनाओं के वित्तपोषण मामले में नियामकीय, संरचनात्मक चुनौतियों, सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षमताओं आदि के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सूचना का आपस में आदान-प्रदान इन संस्थानों के लिए कई अवसर प्रदान कर सकता है। परियोजना तैयारी सुविधाओं जैसी पहलों के माध्यम से ये संस्थान परियोजनाओं को बैंक को स्वीकार्य स्तर तक लाने में सहयोग कर सकते हैं। भारतीय एक्ज़िम बैंक ने अफ्रीकी विकास बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर अफ्रीका में इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में प्राइवेट सेक्टरों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अफ्रीका में कुकुजा परियोजना विकास कंपनी की स्थापना कर इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

लिक्विडिटी क्षमता के सृजन में भी डीएफआई सहयोग कर सकते हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के चलते विशेष रूप से छोटी फर्मों तथा छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को लिक्विडिटी की कमी का सामना करना पड़ा। एमडीबी, राष्ट्रीय डीएफआई और ईसीए द्वारा लिक्विडिटी पूल की स्थापना की जा सकती है। इससे मुद्रा और ऋण में संकुचन के समय एसएमई, नए निर्यातकों और छोटे देशों में फर्मों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध रहेगा और उन्हें लिक्विडिटी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

घरेलू वित्तीय क्षेत्रों में क्षमता निर्माण

स्थानीय वित्तीय क्षेत्रों में क्षमता निर्माण विकासशील देशों में व्यापार वित्तपोषण के बुनियादी ढांचे में सुधार की एक प्रमुख पहल हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उभरते बाजारों की बढ़ती भूमिका और प्रभाव को बहुमुखी उपायों से सहयोग दिया जाना चाहिए। शुरुआत में घरेलू संस्थानों के सुधार की आवश्यकता होगी। कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाजार जोखिम नहीं लेते हैं और इन अर्थव्यवस्थाओं में बैंक की जमापूँजी का एक बड़ा हिस्सा कम प्रतिफल तथा कम जोखिम वाली योजनाओं में निवेश किया जाता है। व्यापार वित्त में मौजूदा चुनौतियों और जोखिमों का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और नीतिगत परामर्श की आवश्यकता होगी। घरेलू वित्तीय क्षेत्र में जड़ता को खत्म करने के लिए भी बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी को अपनाना बहुत आवश्यक है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली ऐसी तकनीकी सहायता जो योजनाओं और तंत्र को मजबूत करती है, व्यापार वित्त को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। व्यापार वित्त का एक बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो सीमापार लेनदेनों, जोखिम मूल्यांकन और कम व्यापार वित्त लागत की दृष्टि से इन संस्थानों की क्षमता सृजन के लिए आवश्यक होती है। संस्थागत क्षमता सृजन में एमडीबी, ईसीए और राष्ट्रीय डीएफआई की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इनमें से कई तो पहले से ही ऐसी तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। बैंकों द्वारा व्यापार वित्त सुविधाओं के साथ-साथ उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना एमडीबी के व्यापार वित्त कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है।

सूचनाओं की कमी को पूरा करने के लिए व्यापार वित्त के प्रमुख एजेंट अर्थात वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ निर्यात वित्त संस्थाओं को भी तकनीकी सहायता प्रदान करना महत्त्वपूर्ण होगा।

निर्यात वित्त संस्थातओं में संस्थागत क्षमता निर्माण उन्हें निर्यात वृद्धि के प्रमुख संचालकों के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी, विशेषकर उन परिदृश्यों में जहां वाणिज्यिक क्षेत्र व्यापार वित्त की मांग को कुशलतापूर्वक पूरा करने में असमर्थ हैं। संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए निर्यात वित्त संस्थाएं पहले से ही विकासशील देशों में कई अन्य निर्यात वित्त संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने में सक्रिय हैं। उदाहरणस्वरूप, भारतीय एक्ज़िम बैंक ने कई देशों में संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं।

बाजार सूचना

यह एक महत्वपूर्ण घटक है कि व्यापार वित्त प्रदाताओं के जोखिम का सटीक मूल्यांकन करने के लिए क्रेडिट जानकारी का संग्रहण किया जाए और उन्हें साझा किया जाए। आयातकों और निर्यातकों की ऋण पात्रता की सही और भरोसेमंद जानकारी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार सहित बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सस्ते उत्पाद प्रस्तुत करने का अवसर दे सकती है। ऐसे कई उपाय हैं जिनके माध्यम से एमडीबी, ईसीए और राष्ट्रीय डीएफआई मजबूत क्रेडिट सूचना प्रणाली के सृजन हेतु देशों और संस्थानों की मदद कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों, विनियामकों आदि को सलाह और सहयोग देकर एक अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है। नए क्रेडिट ब्यूरो और क्रेडिट रजिस्ट्रियों को विकसित करने के लिए देशों को प्रत्यक्ष सहयोग भी प्रदान किया जा सकता है। मौजूदा ब्यूरो को बढ़ाने के लिए भी सहयोग प्रदान किया जा सकता है। आईएफसी अपने वैश्विक क्रेडिट रिपोर्टिंग कार्यक्रम के तहत पहले से ही ऐसी सहायता प्रदान कर रहा है।

बाजार सूचना गैप वित्तीय सेवाओं में भी उत्पन्न होता है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद संपर्की बैंकिंग संबंधों में कमी आई है। व्यापार मॉडल के पुनर्मूल्यांकन से जहां इन संबंधों में गिरावट आई, वहीं ऐसे संबंध भी टूट गए जहां विनियामक अपेक्षाएं अस्पष्ट हैं, जोखिम को कम नहीं किया जा सकता है या जानकारी साझा करने के लिए कानूनी बाधाएं हैं।

पारस्परिक भागीदारी और सहयोग से बाजार सूचना गैप को कम किया जा सकता है। व्यापार वित्त आँकड़ों के लिए देशों के बीच साझेदारी के माध्यम से बाजारों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और जोखिमों से बचा जा सकता है। इससे झटकों और संकटों के दौरान व्यापार वित्त बाजारों में उत्पन्न चुनौतियों को समझने तथा उत्तरदायी समाधान तैयार करने में मदद मिलेंगी।

श्रेष्ठ व टिकाऊ समाधानों का आदान-प्रदान करने में समय लग सकता है, किन्तु अंतरिम समाधान के रूप में करेस्पांडेंट व रेस्पांडेंट बैंकों के बीच सूचना प्रवाह को सुधारा जा सकता है। इसमें "अपने ग्राहक को जानें" जैसे सॉफ़्टवेयर के प्रयोगों का उपयोग शामिल है, जो एक ही स्थांन पर ग्राहकों से संबंधित जानकारी संग्रहीत करता है और सभी बैंक इसका लाभ उठा सकते हैं।

वैकल्पिक व्यापार वित्तपोषण

गैर-बैंक पूँजी धीरे-धीरे व्यापार वित्त के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रही है। वित्तीय संकट के समय से इन्होंने आवश्यक मांग को पूरा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भविष्य में, फिन-टेक और वैकल्पिक वित्त प्रदाताओं की भूमिका व्यापार-वित्त गैप को पाटने में महत्वपूर्ण होगी। वैकल्पिक वित्त प्रदाता तेजी से उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच पीयर-टू-पीयर उधार, जन सहयोग और व्यापार वित्त के लिए इनहाउस ट्रेडिंग जैसे माध्यमों से सीधा सम्बन्ध जोड़ रहे हैं। फिन-टेक कंपनियां बैंकों के जरिए मध्यवर्ती व्यापार वित्त की मौजूदा व्यवस्था को भी मजबूत करती हैं। व्यापार वित्तपोषण में हेज फंड भी सक्रिय हैं। डीएफआई, बैंक और फिन-टेक कंपनियों के बीच भागीदारी वित्त व्यापार को बढ़ाने तथा संबंधित वित्तीय प्रणाली को सुधारने व उसकी कार्य कुशलता को प्रबल करने में सहायता कर सकती है।

व्यापार वित्त सुविधा

विकासशील देशों की विकास वित्त संस्थाएं तथा निर्यात वित्त संस्थाएं व बहुपक्षीय विकास संस्थाएं मिलकर व्यापार वित्त तक पहुँच बढ़ाने के लिए भागीदार देशों के बैंकों और कम्पनियों से व्यापार वित्त सुविधा हेतु संभावनाओं का पता लगा सकती है। कई बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थाओं में पहले से ही जोखिम कम करने वाले उत्पाद हैं, ऐसे में राष्ट्रीय विकास एजेंसियों की भागीदारी से ऐसे उत्पादों के क्षेत्र और विस्तार में काफी वृद्धि हो सकती है। क्षेत्रीय स्तर पर इन सुविधाओं को स्थापित किया जा सकता है। स्थानीय जारीकर्ता बैंकों से लेन-देन करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय बैंकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसी सुविधाएं गैर-वित्त पोषित गारंटी प्रदान कर सकती हैं। ये सुविधाएं व्यापार वित्त भी बढ़ा सकती हैं, जो किसी कम्पनी की व्यापार चक्र अवधि- जोकि कच्चे माल के आयात / खरीद से बिक्री आय की प्राप्ति तक होती है, के अनुसार है। ऐसे ऋण इनवाइस/कारोबार के अनुसार प्रदान किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एल सी और बिल आदि के अंतर्गत पैसा प्राप्त करने में काफी समय लग सकता है। बैंक बाजार मूल्य के आधार पर इन एलसी और बिलों की डिस्काउंटिंग कर पार्टी को धनराशि समय से पहले ही उपलब्ध करा सकते हैं।

यह सुविधा बैंकों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहयोग भी प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, संबंधित सरकार द्वारा बैंकों के अनुपालन से जुड़े मुद्दों की लागत को कवर करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा सकती है।

4 राज्यावलोकन: मध्य प्रदेश

अवलोकन

मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित लैंडलॉक्ड राज्य है, इसकी सीमाएं पांच राज्यों से मिलती हैं। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7.3 % की दर से वृद्धि करते हुए 4991 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो वर्ष 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2016-17 के 4651.4 बिलियन की तुलना में है।

निर्यात परिदृश्य

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के निर्यात में 1.7% की गिरावट दर्ज की गई। निर्यात वर्ष 2012-13 में 4.8 बिलियन यूएस डॉलर से गिरकर वर्ष 2015-16 में 3.96 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। किन्तु वर्ष 2016-17 में यह बढ़कर 4.43 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। वर्ष 2016-17 में कुल भारतीय निर्यात में हिस्सेदारी के मामले में यह राज्य 15 वें स्थान पर रहा।

उत्पाद विश्लेषण

वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश से 10 शीर्ष वस्तुओं का राज्य के कुल निर्यात में लगभग 65.4% हिस्सा रहा।

वर्ष 2016-17 में 6 अंकों के स्तर पर, मध्य प्रदेश से शीर्ष निर्यातित वस्तुओं में 'खुदरा बिक्री' (एचएस कोड- 300490) के लिए मिश्रित या अमिश्रित उत्पादों से युक्त दवाइयां शामिल थीं। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान इनकी वृद्धि दर 48.2% रही। 2016-17 में मध्य प्रदेश से कुल निर्यात में इनका हिस्सा 17.8% और भारत से निर्यात में इनका हिस्साा 8.1% रहा। 2016-17 में इनका निर्यात 2012-13 के 193.3 मिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 789.0 मिलियन यूएस डॉलर हो गया।

इसके बाद सोयाबीन तेल के निष्कर्षण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न 'ऑयलकेक और अन्य ठोस अवशेष (एचएस कोड-230400) का स्था न रहा। 2011-12 से 2016-17 के दौरान इनके निर्यात में 3.6% की दर से वृद्धि दर्ज की गई। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में जहाँ मध्य प्रदेश के कुल निर्यात में इस वस्तु के निर्यात की 6.5% हिस्सेदारी थी वहीं भारत से इन वस्तु ओं के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 51.7% थी।

दरअसल, 2016-17 में मध्य प्रदेश द्वारा निर्यात की गई शीर्ष 10 मदों में 3 अन्य वस्तुएं भी शामिल थीं जिनका भारत से कुल निर्यात में 15% से अधिक हिस्सा था।

इसके अलावा कुछ ऐसी भी मदें हैं जिनमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान मध्य प्रदेश से इस अवधि के दौरान 6 डिजिट कोड वाली शीर्ष 10 वस्तुओं के निर्यातों में काफी तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो इसी अवधि के दौरान 1.7% के मुकाबले 5.7% थी। भारत के कुल निर्यात में 2016-17 में मध्य प्रदेश से निर्यात की गई 6 डिजिट स्तर की शीर्ष 10 मदों की हिस्सेदारी 11.3% थी ।

देश विश्लेषण

वर्ष 2016-17 में देशवार निर्यात विश्लेषण से पता चलता है कि मध्य प्रदेश से वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका (27.6%), बांग्लादेश (7.6%), चीन (4.4%), जर्मनी (3.3%) और जापान (3.2%) हैं। यह रोचक तथ्य है कि ईरान जो 2013-14 में मध्य प्रदेश से निर्यात के लिए सबसे बड़ा और 2014-15 में चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था वह 2015-16 में 33वें तथा 2016-17 में 30वें स्थान पर रहा। इसका प्रमुख कारण प्रतिबंधों के बाद आई ढील के चलते ईरान को अन्य देशों से बढ़ता निर्यात रहा।

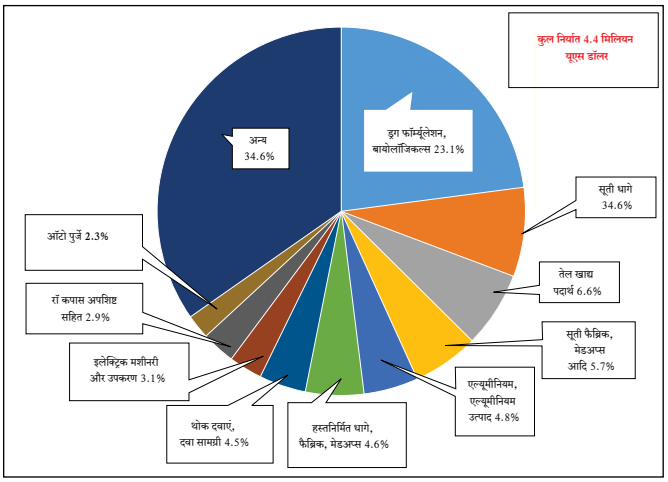

मध्य प्रदेश में एफडीआई

फाइनेंशियल टाइम्स एफडीआई बाजारों के अनुसार, जनवरी 2008 से नवंबर 2017 के दौरान भारत में आए कुल निवेश में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 2.1% थी। इसी अवधि के दौरान, भारत में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी कुल पूँजी व्यय का लगभग 2.3% रही। इन परियोजनाओं में कुल 9.1 बिलियन यू एस डॉलर का पूँजी निवेश किया गया है।

जनवरी 2008 से नवंबर 2017 के दौरान 10 वर्षों की अवधि में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका से थीं। कुल परियोजनाओं में से 24% अमेरिका, इसके बाद जर्मनी 17%; यूके 9%; जापान 9% तथा सिंगापुर 6% का स्थान रहा।

पूँजीगत निवेश के मामले में, ओमान ऑयल कंपनी की सिंगल परियोजना के जरिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 26% पूँजी निवेश किया जा रहा है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 18%; जर्मनी 17%; सिंगापुर 10% तथा स्वीडन 7% का स्थान रहा।

जनवरी 2008 से नवंबर 2017 के दौरान मध्य प्रदेश में अधिकतम ग्रीनफील्ड विदेशी पूँजीगत व्यय कोयला तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में (2.4 अरब यूएस डॉलर) किया गया। इस अवधि के दौरान भारत में किए गए कुल ग्रीनफील्ड विदेशी पूँजी व्यय का यह 6.7% था। अन्य प्रमुख क्षेत्र (एफडीआई के कुल मूल्य के अनुसार) अक्षय ऊर्जा (भारत में इसका हिस्सा 6.7%), सेमीकंडक्टर (34.9%), इलेक्ट्रॉनिक अवयव (1.9%) तथा खनिज 58.7% थे। राज्य को भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कुल निवेश का लगभग 28.5%, मनोरंजन क्षेत्र का 6.4% और भारत के दवाइयों के क्षेत्र में कुल निवेश का 6.1% हिस्साा रहा।

आगे की राह

यह देखा गया है कि लैंडलॉक्ड प्रदेश हरियाणा (3.9%) और पंजाब (1.9%), मध्य प्रदेश से छोटे राज्य हैं। इन राज्यों का 2016-17 में मध्य प्रदेश की तुलना में भारत से निर्यात में अधिक योगदान रहा है। राज्य में इस गैप को अपनी संसाधन विविधता और मजबूत उत्पादन नेटवर्क के जरिए कम करने की क्षमता है।

उत्तर प्रदेश कई दशकों से पूरे देश की संस्कृतियों, धर्मों और व्यवसायों का संगम रहा है। उत्तर प्रदेश लगभग 95000 वर्ग मील (246,000 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र में फैला हुआ भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। विभिन्न प्रकार के संसाधनों से संपन्न, विविध प्रकार के उत्पादन करने वाले तथा मूल्यसंवर्धक नेटवर्कों के जरिए उत्तर प्रदेश का भारत के निर्यातों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान सभी राज्यों में मूल्य की दृष्टि से निर्यात में उत्तर प्रदेश का पाँचवा स्थान रहा।

लैंडलॉक्ड राज्य उत्तर प्रदेश को एक निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मांग रुझानों के साथ कुछ विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी और केंद्र सरकार द्वारा किए गए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार करारों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु ध्यान देना होगा।

आज के समय में वैश्विक व्यापार अत्यधिक अप्रत्याशित और डायनेमिक हो गया है, जिसपर विभिन्न व्यवधान, प्रतिस्पर्धा और बदलती प्राथमिकताओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने एवं उसमें स्थिरता लाने के लिए निर्यात रणनीति को सदृढ़ करने तथा राज्य के औद्योगिक और आर्थिक आधारभूत संरचना को संशोधित और आधुनिकीकृत किया जाना जरूरी है। राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी रणनीति के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सकता है:

इंफ्रास्ट्रक्चर

निर्यात इकाइयों के प्रभावी निष्पादन के लिए कच्चे माल आपूर्तिकर्ताओं और फिर तैयार माल को बेचने के लिए बाज़ारों (फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज़) की मजबूत आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी। इसमें हवाई अड्डे, सूखे बंदरगाह, कंटेनर स्टेशन्स, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, गोदाम, कृषि-गोदाम, फसल प्रसंस्करण सुविधाएं, पैकेजिंग सुविधाएं, निर्यात उत्पाद प्रदर्शनी केंद्र, फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल के लिए माल बैंक, बहुस्तरीय लॉजिस्टिक्स केंद्र, और विशेष औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।

उत्कृष्ट निर्यातक पुरस्कार पहल

राज्य सरकार अभिनव प्रयासों के माध्यम से उत्पादों के निर्यात में अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले, छोटे उद्यमों को चिह्नित करने, प्रोत्साहित करने और उनकी सराहना के लिए 'उत्कृष्ट निर्यातक पुरस्कार' पहल शुरू कर सकती है। यह प्रयास राज्य अर्थव्यवस्था में नवाचार को प्रोत्साहित कर सकता है। इस पहल के तहत, चुनिंदा कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी एसएमई से प्रतियोगिता करने के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है।

विशिष्ट उत्पादों के लिए भोगौलिक उपदर्शन (जीआई)

उत्तर प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों के लिए जी आई ब्रांड के चिह्न और नाम विकसित किए जाने और उनका प्रचार किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता है कि भौगोलिक संकेत ब्रांड के तहत विपणन किए गए सभी उत्पाद न्यूनतम निर्दिष्ट मानकों को पूरा करते हैं। इसके लिए, उद्योग विभाग द्वारा अपने विभाग के तहत एक ब्रांड इक्विटी फंड स्थापित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य राज्य से उत्पन्न उत्पादित / उत्पादित उत्पादों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी ब्रांडों का निर्माण करना है।

ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना

परिधान, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, कालीन आदि जैसे परंपरागत रूप से मजबूत क्षेत्रों में इंटरनेट के माध्यम से व्यापार के अवसरों को अभी पूरी तरह दोहित करना बाकी है। इन उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाजार इन उत्पादों की पहुंच में काफी वृद्धि कर सकते हैं और उत्पादकों को बेहतर कीमत दिला सकते हैं।

क्लस्टर विकास

उत्तर प्रदेश में कई औद्योगिक क्लस्टर हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। क्लस्टर का विकास और उन्नयन राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। इन क्लस्टरों का आकलन कर सरकार द्वारा इनमें जरूरी क्षमता निर्माण किया जा सकता है। क्षमता निर्माण में भौतिक आधारभूत संरचना निर्माण, भवन निर्माण संस्थागत विकास, मानव संसाधनों का विकास आदि शामिल हैं।

मांस प्रसंस्करण

अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए, राज्य को अपने पुराने बूचड़खानों को आधुनिक बनाने तथा इनमें सभी बुनियादी और न्यूनतम स्वच्छता मानकों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। राज्य अपने 'खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम' को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है।

कालीन

राज्य नवीनतम रंगों, स्वरूपों, नई रंगाई प्रौद्योगिकियों, रंग संयोजन आदि की प्रक्रिया को समन्वयित करने के लिए एक डिजाइन केंद्र स्थापित कर सकता है। इससे बदलती उपभोक्ता जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने में मदद मिलेगी। स्थानीय कालीनों का उचित प्रचार, विशेष रूप से भदोही के कालीन जिनके पास जी आई स्टेटस तो है किन्तु यह उद्योग बाल श्रम जैसे मुद्दे पर प्रतिकूल प्रचार का सामना कर रहा है, की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

चमड़ा उद्योग

पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए, राज्य को चमड़े के कारखानों के प्रदूषण को रोकने के लिए शहरव्यापी प्रदूषण उपचार संयंत्रों में तत्काल निवेश की आवश्यकता है। एज़ो डाइज और पेंटाक्लोरोफेनॉल के सस्ते विकल्प पर अनुसंधान जिन्हें उनकी कैंसरजन्य प्रकृति के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है, भी महत्वपूर्ण होगा। एक बार उत्पादों को पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप बनाया जा सके फिर 'इको-लेबल्स' जैसे हॉलमार्क के साथ इनका पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के रूप में विपणन किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम क्षेत्र

उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य भर में बिगडाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि जैसे विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा, गाजियाबाद और लखनऊ में 'प्लग एन प्ले मॉडल' आधारित सूचना प्रौद्योगिकी उपवन पहल के तहत स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने और उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए शुरू किए गए इन्क्यूबेशन सेंटर सुविधा को अन्य शहरों में भी विस्तारित किया जा सकता है। राज्य के भीतर अधिक स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम क्षेत्र का विविधीकरण राज्य अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक हो सकता है।

विशेष कवरेज: 13 वां सीआईआई–एक्ज़िम बैंक भारत–अफ्रीका भागीदारी सम्मेलन

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर नई दिल्ली में 25–27 मार्च के दौरान 13वें भारत–अफ्रीका परियोजना भागीदारी सम्मेलन का आयोजन किया। पहला सम्मेलन 2005 में हुआ था और तब से यह सम्मेलन भारत–अफ्रीका के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और सहभागिता बनाने के क्रम में प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। इस सम्मेलन के जरिए अफ्रीकी बाजारों में भारतीय परियोजना निर्यातों को बढ़ाने में भी मदद मिली है। आज भारत–अफ्रीका के आर्थिक संबंधों को इन सम्मेलनों में होने वाले विचारों के आदान–प्रदान की कसौटी के रूप में देखा जा सकता है। इस सम्मेलन में भारत और अफ्रीका से महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिनकी इन दोनों क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय में अहम भूमिका रही है।

13 वें सम्मेलन का उद्घाटन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा किया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि भारत–अफ्रीका के बीच वर्तमान व्यापार 53 मिलियन यूएस डॉलर का है, लेकिन इसे बढ़ाए जाने और बाजार में विशाखन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर भी वार्ता की जाएगी, जो अपनी तरह की अनूठी पहल होगी और अफ्रीका को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार एक नया भारत–अफ्रीका विकास कोष बनाने के बारे में विचार कर रही है। इससे अफ्रीका को दी जाने वाली ऋण–व्यवस्थाओं और अन्य निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय और महाद्वीप के चहुंमुखी विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि अफ्रीका को भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय निर्यात बीमा और परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद में भी कुछ परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नागरिक उड्डयन क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में भारत–अफ्रीका को जोड़ने और विशिष्ट योजक सूत्रों को मजबूत करने की सरकार की मंशा का भी उल्लेख किया।

इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर तीन अफ्रीकी देशों के उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इनमें मलावी के माननीय उपराष्ट्रपति डॉ. साउलोस क्लॉस शिलिमा, यूगांडा के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एवार्ड स्सेकंदी, जिम्बाब्वे के माननीय उपराष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. कंस्टैन्टिनो जी.एन.डी. शिवेंगा शामिल हैं। तीनों उपराष्ट्रपतियों ने वर्तमान भारत–अफ्रीकी भागीदारी और अपने–अपने देशों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की जरूरत का उल्लेख किया।

13वें सम्मेलन में एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन का विमोचन

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन 'कनेक्टिंग अफ्रीका: परिवहन अवसंरचना की भूमिका' का विमोचन किया। इसके साथ ही अफ्रीका और सीआईआई के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा 'बढ़ती अफ्रीका–भारत व्यापार एवं निवेश साझेदारी' शीर्षक वाली एक संयुक्त रिपोर्ट तथा अफ्रीका में भारतीय कंपनियों द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के संकलन का भी विमोचन किया गया। एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन में अफ्रीका की परिवहन व्यवस्था की मौजूदा स्थिति और इसके विकास में आने वाली चुनौतियों तथा इस महाद्वीप में परिवहन नेटवर्क और संपर्क बढ़ाने के लिए रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है। उद्घाटन के दौरान एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना और इकोवास बैंक फॉर इंवेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के माननीय प्रेसिडेंट श्री बशीर एम आईएफओ द्वारा 500 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण–व्यवस्था करार पर भी हस्ताक्षर किए गए। एक्ज़िम बैंक द्वारा यह ऋण–व्यवस्था इकोवास क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई है। समापन सत्र के दौरान वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सी.आर. चौधरी ने उम्मीद जताई कि अफ्रीकी क्षेत्र द्वारा भारतीय डीएफपीटी योजना के बेहतर इस्तेमाल से अगले पांच वर्षों में भारत–अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार 150 अरब यूएस डॉलर तक पहुंच सकता है।

यह सम्मेलन व्यापार, निवेश और विकास के अपने लक्ष्यों को हासिल करने में इन मायनों में भी सफल रहा कि इसके जरिए भारतीय और अफ्रीकी कारोबारियों तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अतंर्गत जुड़ने का अवसर मिला। सम्मेलन के दौरान भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार, निवेश, इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्षमता निर्माण कृषि विकास और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

संक्षिप्त विवरण

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने देश की अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर नई दिल्ली स्थित आईटीसी मौर्य होटल में 20-22 फरवरी, 2018 के दौरान एशिया-प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संगठन (एडफिएप) की 41वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की। एडफिएप एशिया-प्रशांत क्षेत्र के तमाम विकास बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं का केंद्र है। इस क्षेत्र से 98 विकास वित्त संस्थाएं इसकी सदस्य हैं। एडफिएप की वार्षिक आम बैठक को इस संगठन के एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। यह बैठक इसकी सभी सदस्य संस्थाओं, भागीदारों और सहयोगी संस्थाओं के लिए अपने-अपने अनुभव बांटते हुए उनसे सीखने और व्यवसाय नेटवर्किंग के लिए साझे मंच का काम करती है। बैठक में सदस्य संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

व्यापार वित्त पर पूर्ण सत्र

वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित विभिन्न पूर्ण सत्र इस क्षेत्र की भारतीय वित्तीय संस्थाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण साझे विषयों पर चर्चा के माध्यम बने। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक विकास के विस्तार में व्यापार वित्त की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एक्ज़िम बैंक ने लचीली व्यापार वित्त व्यवस्था पर भी एक पूर्ण सत्र का आयोजन किया।

इस सत्र के दौरान संगठन के सदस्यों और क्षेत्र के विशेषज्ञों ने एशिया प्रशांत में अंतः क्षेत्रीय व्यापार में तेजी लाने वाले उभरते व्यापार वित्त परिदृश्य और इसकी चुनौतियों सहित व्यापार वित्त को बढ़ावा देने के विभिन्न नवोन्मेषी, समावेशी और एकीकृत समाधानों पर चर्चा की। सत्र में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की विभिन्न विकास वित्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। इस प्रकार यह सत्र व्यापार वित्त संबंधी विभिन्न विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिहाज से सार्थक रहा। यह पहल भविष्य में व्यापार वित्त के क्षेत्र में बहुपक्षीय भागीदारी को आगे बढ़ाएगी।

एक्ज़िम बैंक के प्रकाशनों का विमोचन

वार्षिक बैठक के दौरान एक्ज़िम बैंक के दो प्रकाशनों का विमोचन किया गया। श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, भारत सरकार द्वारा बैठक के उद्घाटन सत्र के दौरान एक्ज़िम बैंक के 'व्यापार वित्त को बढ़ावा: विकास बैंकों और निर्यात ऋण एजेंसियों की अग्रणी भूमिका' शीर्षक वाले शोध अध्ययन का विमोचन किया गया। इस शोध अध्ययन में कहा गया है कि व्यापार वित्त की कमी को पूरा करने और निजी वित्त में तेजी लाने में बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी), निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) और राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) की अहम भूमिका होगी।

एक्ज़िम बैंक का दूसरा प्रकाशन ''लचीली व्यापार वित्त व्यवस्था का निर्माण: आलेखों का संकलन'' का विमोचन वार्षिक बैठक के समापन सत्र में श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। इसमें व्यापार वित्त में आने वाली बाधाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही व्यापार वित्त बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी, समावेशी और एकीकृत रणनीतियां बताई गई है, जिससे अंततः वैश्विक व्यापार भी बढ़ेगा। इस संकलन में इस क्षेत्र के अग्रणी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए 12 आलेख / शोध पत्र शामिल हैं।

एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन ''व्यापार वित्त को बढ़ावा: विकास बैंकों और निर्यात ऋण एजेंसियों की अग्रणी भूमिका'' में व्यापार वित्त के क्षेत्र में हालिया रुझानों, व्यापार वित्त प्रवाह से जुड़ी चुनौतियों और वैश्विक व्यापार वित्त में बड़े घाटे को कम करने के लिए अपनाई जा सकने वाली रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है। एक आकलन के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक व्यापार वित्त में 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अंतर है, जिसमें से 40% एशिया प्रशांत में है। अध्ययन के अनुसार, विकासशील देशों में व्यापार वित्त का यह अंतर वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बढ़ा है। अध्ययन में वित्तपोषण की शर्तों को नरम बनाने और व्यापार वित्त को सुगम बनाने में निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप, व्यापार ट्रांजैक्शनों में निर्यात ऋण एजेंसियों की सहभागिता से यह सुनिश्चित किया जा सका है कि निर्यातक जोखिम भरे परिवेश में भी अपने माल और सेवाएं ओपन अकाउंट शर्तों पर दे पाएं।

प्रमुख परिणाम

एडफिएप की वार्षिक बैठक एशिया-प्रशांत क्षेत्र की विकास वित्त संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्षेत्रीय सहयोग के जरिए न केवल घरेलू विकास के प्रयासों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि इस बैठक में भाग लेने वाले देशों के लिए उपलब्ध विकल्पों को भी विस्तार मिलता है। भारत सरकार ने विशेष रूप से एशियाई क्षेत्र के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। 1992 में सरकार ने समुद्री दक्षिणपूर्व एशिया-प्रशांत क्षेत्र से मजबूत संबंधों के लिए 'लुक ईस्ट पॉलिसी' बनाई थी। अब यह नीति अपने और अधिक सक्रिय रूप में 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में तब्दील हो गई है, जो तेजी से उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच बहु-पक्षीय संपर्क को बढ़ावा देती है। एडफिएप वार्षिक बैठकें इस क्षेत्र में उभरते सहयोग के लिए लाभकारी साबित हुई हैं और एडएफिएप वार्षिक बैठक की मेजबानी ने विकास वित्त के क्षेत्र में भारत की भूमिका को नए आयाम प्रदान किए हैं।

आर्थिक सर्वे 2017–18: संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार द्वारा जनवरी 2018 में जारी वार्षिक आर्थिक सर्वे में आगामी कुछ महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जताई गई है। सर्वे में जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2018 की 6.6% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019 में 7 से 7.75% तक रहने का अनुमान लगाया गया है।

सर्वे में पहली बार निर्यात निष्पादन और राज्य के जीवन स्तर के बीच मजबूत सह-संबंधों को दर्शाया गया है। सर्वे में कहा गया है कि निर्यात में जिन राज्यों की हिस्सेदारी अधिक है, वहां जीवन स्तर भी बेहतर है। सर्वे के अनुसार, भारत के निर्यात में पांच राज्यों- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का 70% हिस्सा है। इसमें यह उल्लेख भी किया गया है कि दूसरे देशों के विपरीत भारत के निर्यात कारोबार में 38% हिस्सा भारतीय कंपनियों में से शीर्ष 1% का ही है, जबकि ब्राजील, जर्मनी, मेक्सिको और यूएसए में यह स्थिति क्रमशः 72%, 68%, 67% और 55% है। शीर्ष 5-10% भारतीय कंपनियों में भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई है।

सर्वे में यह भी उल्लेख किया गया है कि वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात के मामले में 2016 में भारत 3.4% हिस्से के साथ आठवां सबसे बड़ा निर्यातक देश बना रहा। यह विश्व में भारत के वस्तु निर्यात 1.7% से दोगुना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख संकेतकों (चुनिंदा को यहां ग्राफ में दर्शाया गया है) के विवरण के अलावा सर्वे में वित्तीय क्षेत्र में भारतीय दिवाला संहिता (आईबीसी) का उल्लेख भी किया गया है, जिसे कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट दुरुस्त करने और अपने ऋण कम करने के समाधान में मददगार माना जा रहा है।

विश्व बैंक की कारोबार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस) रिपोर्ट में भारत के 130 से उठकर 100 वें स्थान पर आने पर संतोष जाहिर किया गया है। यद्यपि भारत ने सभी मानदंडों में सुधार दर्ज किया है, तथापि 'कर भुगतान', 'ऋण प्राप्ति' और 'दिवालिया समाधान' जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।

हालांकि भारत को विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू करने में आई दिक्कतों के चलते कुछ अस्थिरता का सामना करना पड़ा, जिसके अंततः खत्म होने की संभावना है। सर्वे में निजी निवेश बढ़ने और 14 वर्ष में पहली बार रेटिंग बढ़कर बीएए 2 होने की भी उम्मीद जताई गई है।

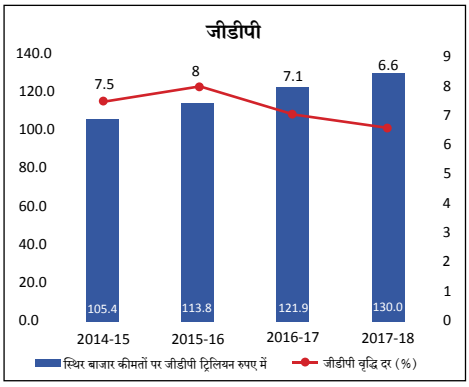

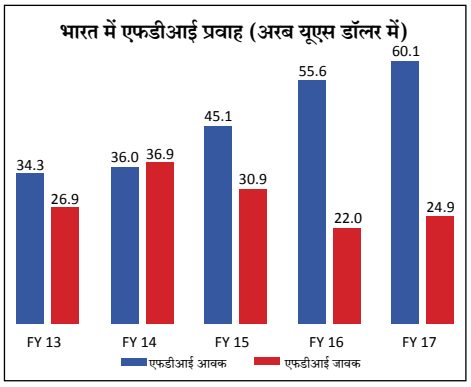

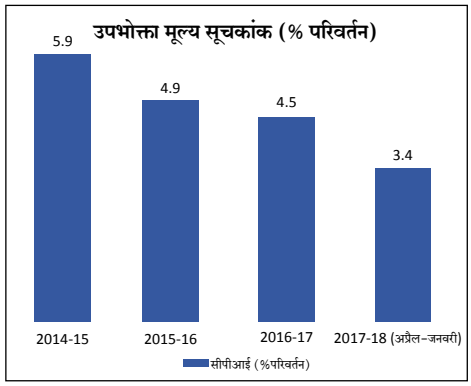

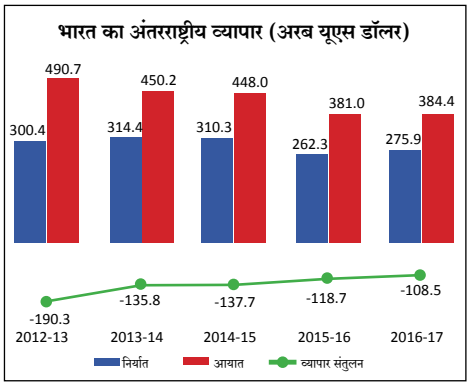

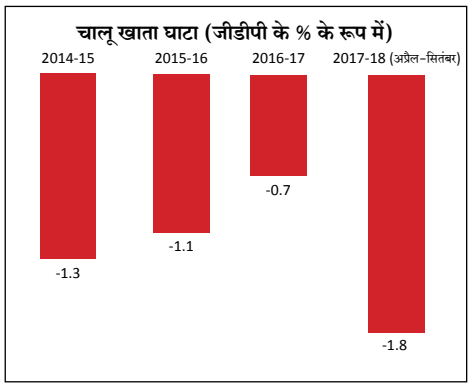

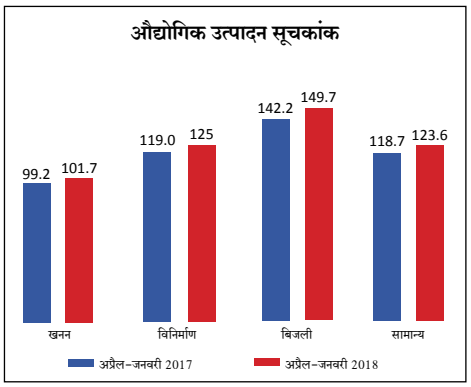

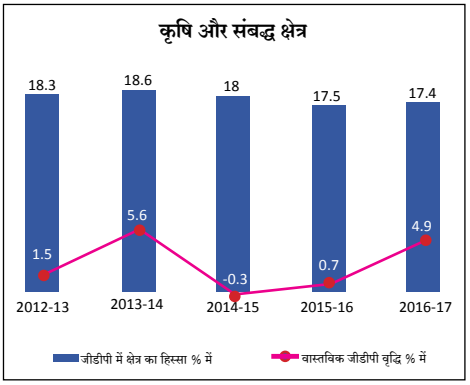

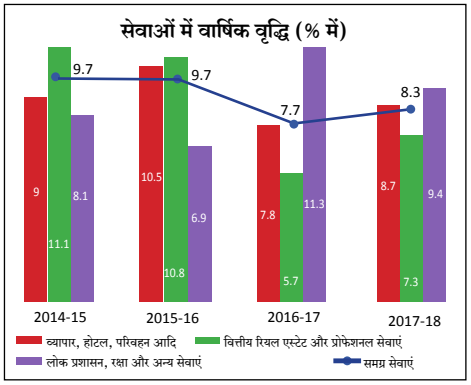

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आरबीआई

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मध्यम उद्यमों पर विशेष बल के साथ भावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है। ये ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातक समुदाय को जोखिम और दायित्व रहित निर्यात वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करती हैं, जो उन्हें नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने और मौजूदा विदेशी बाजारों में निर्यात बढ़ाने में मदद करती हैं। एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है।

हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं।

बैंक द्वारा अब तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका ओशिनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 21.37 अरब यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 225 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्द्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से जनवरी-मार्च, 2018 की अवधि के दौरान निम्नलिखित तीन ऋण-व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए:

(i) भारत सरकार की ओर से जाम्बिया सरकार को 18 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण-व्यवस्था जाम्बिया में स्वास्थ्य केंद्रों के लिए दी गई है। इस ऋण-व्यवस्था करार सहित एक्ज़िम बैंक अब तक जाम्बिया सरकार को भारत सरकार की ओर से कुल 107.03 मिलियन यूएस डॉलर की चार ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कर चुका है। जाम्बिया सरकार को ये ऋण-व्यवस्थाएं इतेझी-तेझी जलविद्युत परियोजना, बसों, मोटर वाहनों, मोटर साइकिलों के निर्यात और व्यावसायिक टूल किट्स की आपूर्ति के लिए प्रदान की गई हैं।

(ii) भारत सरकार की ओर से कंबोडिया सरकार को 32.92 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण-व्यवस्था कंबोडिया में स्तुंग स्वा हैब / स्लैब जल संसाधन विकास परियोजना के वित्तपोषण के लिए दी गई है। इस ऋण-व्यवस्था करार सहित एक्ज़िम बैंक अब तक कंबोडिया सरकार को भारत सरकार की ओर से कुल 102.12 मिलियन यूएस डॉलर की चार ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कर चुका है। कंबोडिया सरकार को ये ऋण-व्यवस्थाएं स्तुंग-तसल विकास परियोजना, क्रेटी और स्तुंग ट्रेंग के बीच ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

(iii) भारत सरकार की ओर से श्रीलंका सरकार को 45.27 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण-व्यवस्था श्रीलंका में कांकेसंथुराई हार्बर में पुनर्वास परियोजना के वित्तपोषण के लिए दी गई है। इस ऋण-व्यवस्था करार सहित एक्ज़िम बैंक अब तक श्रीलंका सरकार को भारत सरकार की ओर से कुल 1.58 अरब यूएस डॉलर की आठ ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कर चुका है। श्रीलंका सरकार को ये ऋण-व्यवस्थाएं उपकरणों की खरीद/आपूर्ति, कोलंबो से मतारा तक दक्षिणी रेलवे कॉरिडोर के उन्नयन, श्रीलंकाई रेलवे तथा अन्य रेलवे परियोजनाओं के लिए रोलिंग स्टॉक की खरीद के लिए प्रदान की गई हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

श्री नदीम पंजेतन,
मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, स्टेट्समैन हाउस, तल मंज़िल, 148 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001
टेलीफोनः (011) 23474851
फैक्सःन (22) 22823394
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

सफलता की कहानी: स्वाजीलैंड

- एक्ज़िम बैंक द्वारा स्वाजीलैंड सरकार को नवंबर 2017 में कृषि विकास और कृषि के मशीनीकरण के लिए 37.90 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई थी।
- परियोजना नवंबर 2017 में पूरी हुई।
- खाद्य संरक्षा परियोजना से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा अधिक वर्षा वाले इलाकों में फसलों के उत्पादन को लेकर वांछित परिणाम मिले हैं।
- परियोजना के जरिए मंत्रालय के लिए भी महत्त्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना सक्षम हो सका है, जिससे देश में खाद्य संरक्षा की स्थिति में सुधार आएगा।

आसियान के लिए भारतीय मिशन के साथ एक्ज़िम बैंक का संयुक्त शोध अध्ययन, आसियान–भारत सहयोग के रुझानों और भावी संभावनाओं का विश्लेषण

एक्ज़िम बैंक द्वारा आसियान के लिए भारतीय मिशन के साथ मिलकर 'आसियान–भारत सहयोग का सुदृढ़ीकरणः ट्रेंड और भावी संभावनाएं' शीर्षक से संयुक्त शोध अध्ययन किया गया। इसका विमोचन 22 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित आसियान–भारत व्यापार एवं निवेश सम्मेलन के दौरान श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार, द्वारा किया गया।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) की स्थापना 1967 में हुई थी। 2017 में इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए। बीते 5 दशकों के दौरान, आसियान दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बनकर उभरा है तथा अंतः आसियान सहयोग एवं आसियान क्षेत्र में विकास को बढ़ाते हुए आर्थिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की है। एक्ज़िम बैंक के इस शोध अध्ययन में आसियान सदस्य देशों के भारत के लिए रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए उन देशों में भारत के व्यापार एवं निवेश के लिए हालिया रुझानों तथा भावी संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है।

एक्ज़िम बैंक ने 3.875% प्रति वर्ष की कूपन दर पर 10 साल के लिए जुटाए 1 अरब यूएस डॉलर

भारतीय निर्यात–आयात बैंक ने 25 जनवरी, 2018 को 1 अरब यूएस डॉलर का 10 वर्षीय बॉन्ड निर्गम (इश्यू) सफलतापूर्वक जारी किया। यह 144/ए रेग एस फॉर्मैट में बैंक का दूसरा बॉन्ड है। जुलाई 2016 में जारी इतनी ही राशि का यह बॉन्ड भारतीय निर्यात–आयात बैंक के लिए सबसे बड़ा निर्गम था। निर्गम को 100 से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक निवेशकों से कुल 1.8 अरब यूएस डॉलर का अभिदान मिला, जो निर्गम के आकार से 1.8 गुना ज्यादा है। निर्गम से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल दीर्घावधि ऋणों और ऋण–व्यवस्थाओं के माध्यम से भारतीय परियोजना निर्यातों तथा विदेश में निवेश को सहयोग करने के लिए किया जाएगा।

''निर्यात स्पर्धात्मकता के लिए पूर्वोत्तर भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में क्षमता सृजन'' संबंधी परियोजना के वित्तपोषण के लिए यूएनडीपी और एक्ज़िम बैंक के बीच करार पर हस्ताक्षर

एक्ज़िम बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के बीच एक्ज़िम बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में 22 फरवरी, 2018 को निर्यात स्पर्धात्मकता के लिए पूर्वोत्तर भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में क्षमता सृजन संबंधी परियोजना के वित्तपोषण के लिए करार हुआ। करार पर एक्ज़िम बैंक की ओर से प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना और यूएनडीपी की ओर से और सुश्री मैरीना वाल्टर, कंट्री डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

परियोजना का मकसद पूर्वोत्तर से निर्यातों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और युवाओं तथा महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत करना है। इसके लिए प्रमुख रणनीति होगी– भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट नीति' के अंतर्गत उभरते अवसरों का लाभ उठाना। इस नीति के अंतर्गत अन्य के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों, जलविद्युत, एशियाई देशों से नजदीकी जैसे मामलों में क्षेत्र में विद्यमान संभावनाओं को चिह्नित किया गया है।

''तेल की कीमत एवं पेट्रोलियम क्रूड व उत्पादों में अंतरराष्ट्रीय व्यापारः भारतीय परिदृश्य'' नामक एक्ज़िम बैंक का अध्ययन

एक्ज़िम बैंक द्वारा हाल ही में ''तेल की कीमत एवं पेट्रोलियम क्रूड व उत्पादों में अंतरराष्ट्रीय व्यापारः भारतीय परिदृश्य'' नामक एक शोध अध्ययन प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में तेल कीमतों के उतार–चढ़ाव प्रवृत्ति के विश्लेषण के साथ–साथ इसके कारण एवं परिणाम तथा क्रूड एवं पेट्रोलियम उत्पारदों का भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि कमोडिटी बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव, विशेष रूप से अल्पकालिक रूप में, बाजार के रुझानों और उम्मीदों पर निर्भर होता है। वहीं दूसरी ओर, कीमतों में दीर्घकालीन रुझान प्रायः मांग तथा आपूर्ति की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अध्ययन के अनुसार जून 2014 के बाद क्रूड तेल में भारी गिरावट, दोनों तरह के कारणों का संयुक्त परिणाम थी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मांग और आपूर्ति में परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं था किन्तु ओपेक के उद्देश्यों में महत्वपूर्ण बदलाव, भू–राजनीतिक जोखिमों में कमी और यू एस डॉलर में मूल्य वृद्धि जैसे कुछ अन्य घटनाक्रम तेल की कीमतों में गिरावट का प्रमुख कारक बने।

नई दिल्ली में आयोजित ''आसियान–भारत व्यवसाय एवं निवेश सम्मेलन एवं एक्सपो'' के दौरान माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन का विमोचन।

भारत–एस्टोनिया संबंधों का इतिहास काफी पुराना है। दोनों देशों के संबंध तब से हैं, जब 22 सितंबर, 1921 को एस्टोनिया को राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) में शामिल किया गया। 9 सितंबर, 1991 को भारत ने एस्टोनिया को पुनः मान्यता दी और उसी साल हेलसिंकी में 2 दिसंबर को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की नींव पड़ी। तब से ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध मधुर और मित्रतापूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार पर 14 अक्टूबर, 1993 को हस्ताक्षर हुए और यह 13 मार्च, 2000 को लागू हुआ।

पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत और एस्टोनिया के बीच कुल व्यापार 2007–08 के 79.4 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2016–17 में 200 मिलियन यूएस डॉलर हो गया। इसी तरह भारत से एस्टोनिया को निर्यात भी 2017–08 के 68.6 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2016–17 में 97.5 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया। एस्टोनिया से भारत का आयात भी 2007–08 के 10.7 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2016–17 में 102.5 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया। द्विपक्षीय व्यापार के तुलनात्मक रूप से कम रहने के पीछे प्रमुख कारण व्यापार का यूरोपीय संघ के दूसरे देशों के माध्यम से होना है। व्यापार का मूल्य एस्टोनियाई पल्प और कागज की दूसरे देशों के मुकाबले तुलनात्मक कीमतों पर भी निर्भर करता है। 2011–12 के दौरान एस्टोनिया से आयात सबसे अधिक रहा, जो 348.2 मिलियन यूएस डॉलर का था, क्योंकि इस साल उर्वरकों और इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपकरण का आयात बढ़ गया था।

2016–17 के दौरान भारत से एस्टोनिया को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में बिना बुने अथवा बिना कढ़ाई किए हुए वस्त्र एवं परिधान (अपैरल और क्लोदिंग) एसेसरीज़ (17.9%), इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण (17.7%), बुने हुए या कढ़ाई किए हुए वस्त्र एवं परिधान (17.1%), लौह और स्टील (6.2%) तथा कॉफी, चाय और मसाले (4.2%) शामिल रहे।

2016–17 के दौरान भारत द्वारा एस्टोनिया से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में उर्वरक (27.3%), इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण (21.2%), सब्जियां और जड़ी–बूटियां (18.1%), लकड़ी का पल्प और अन्य फाइबर सेल्यूलोसिक सामग्री (15.9%) और लकड़ी की अन्य वस्तुएं (5.3%) शामिल रहीं।

भारत जैसे विशाल देश और तेजी से बढ़ती इसकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग की बेहतर संभावनाएं हैं।

भारत–एस्टोनिया का द्विपक्षीय व्यापार

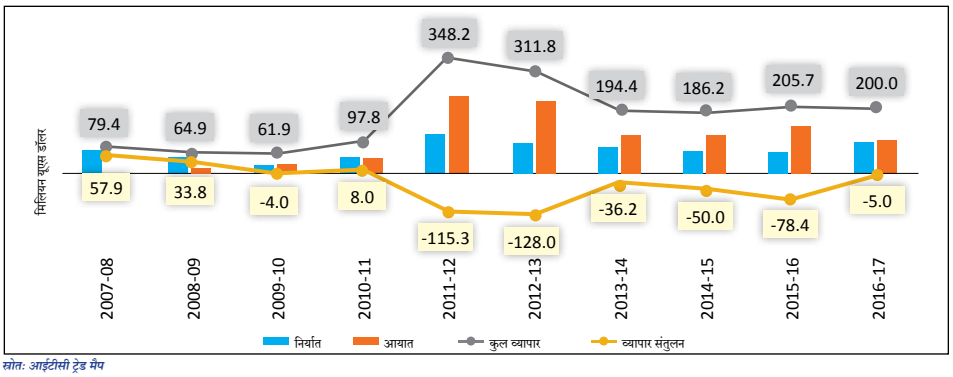

स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप

जहां तक निवेश की बात है तो विकास की काफी संभावनाएं हैं। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2017 के दौरान एस्टोनिया द्वारा भारत में 1.1 मिलियन यूएस डॉलर का कुल निवेश किया गया। एस्टोनियाई कंपनियों द्वारा मुख्य रूप से वित्त, बीमा और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश किया गया। अप्रैल 1996 से दिसंबर 2017 के दौरान संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्थाओं में एस्टोनिया में कुल भारतीय एफडीआई 0.1 मिलियन यूएस डॉलर रहा। भारतीय कंपनियों ने एस्टोनिया में विनिर्माण, निर्माण, होटल, रियल एस्टेट तथा वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है।

दोनों देशों के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए अथवा निम्नलिखित क्षेत्रों में द्वपक्षीय सहयोग की सहमति बनी–

- एस्टोनिया और भारत के बीच सहयोग सिद्धांतों की घोषणा (हस्ताक्षर और लागू होने की तारीख 15 अक्टूबर, 1993);
- व्यापार एवं आर्थिक सहयोग करार (15 अक्टूबर, 1993 को हस्ताक्षर और 24 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी);
- आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार (14 अक्टूबर, 1993 को हस्ताक्षर और 13 मार्च, 2000 से प्रभावी);
- द्विपक्षीय विदेश कार्यालय परामर्शों संबंधी प्रोटोकॉल (अगस्त 1995 में हस्ताक्षर);
- संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला, जन मीडिया, पर्यटन और युवा मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर करार (15 अक्टूबर, 1993 को हस्ताक्षर और 11 नवंबर, 1999 से प्रभावी);
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग करार (5 फरवरी, 1999 को हस्ताक्षर और 6 अगस्त, 1999 से प्रभावी);
- फिक्की और एस्टोनियाई चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच संयुक्त व्यवसाय परिषद करार;
- दोहरे कराधान से बचाव एवं राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए 19 सितंबर, 2011 को समझौते पर हस्ताक्षर;
- बायोटेक्नोलॉजी और उच्च शिक्षा में सहयोग पर अक्टूबर 2013 में सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर;
- ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए फरवरी 2014 में सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर;
- दोषी करार दिए गए अभियुक्तों के हस्तांतरण संबंधी समझौते पर 15 नवंबर, 2016 को हस्ताक्षर और 1 मार्च 2017 से प्रभावी।

ग्रासरूट क्षेत्र को सहयोग

बैंक ने मुंबई, बेंगलूरु, चेन्नै, कोलकाता और पुणे में एक परंपरागत और लोक-कला प्रदर्शनी के लिए सहयोग प्रदान किया। इसका उद्देश्य कारीगरों और दस्तकारों को नए बाजार तलाशने में मदद करना और उन्हें अपने उत्पादों के बड़ी संख्या में मौजूद संभावित खरीदारों तक पहुंचाना था। बैंक ने कुचाई सिल्क एक्सपो, सूरजकुंड मेले और कालाघोड़ा कला महोत्सव में भी कई शिल्पियों को हिस्सा लेने के लिए स्पॉन्सर किया और उन्हें सहयोग प्रदान किया।

इस अवधि के दौरान बैंक द्वारा साशा एसोसिएशन फॉर क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स (साशा) को सहयोग प्रदान किया गया और इसके शिल्पियों के लिए 25 दिन का डिजाइन एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कांथा कढ़ाई करने वाली करीब 20 महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम जयपोर ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (जयपोर) के साथ मिलकर आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य इन महिलाओं को कांथा कढ़ाई में आधुनिक तकनीकों और डिजाइनों का हुनर सिखाना है, ताकि वे आधुनिक डिजाइनों वाले उत्पाद विकसित कर सकें। कार्यक्रम का मकसद अर्द्ध-कुशल महिला शिल्पियों को सशक्त बनाते हुए इस क्षेत्र में रोजगार सृजन करना और नए बाजार अवसर प्रदान करना है।

साशा और जयपोर, एक्ज़िम बैंक के साथ मिलकर डिजाइन विकास के जरिए कांथा उत्पादों के बाजार को विस्तार देने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे उत्पादों के विशाखन में भी मदद मिलेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विकसित किए गए उत्पाद, प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद जयपोर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

बैंक ने पश्चिम बंगाल से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत, अन्य प्रयासों के साथ-साथ बैंक, पश्चिम बंगाल से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए इस राज्य से अपना कारोबार चलाने वाले निर्यातकों के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाते हुए उपयुक्त भागीदारों को चिह्नित कर और उनके लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित कर निर्यात बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा। एमओयू के संबंध में, बैंक ने अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के अंतर्गत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया और पश्चिम बंगाल के शिल्पकारों को कौशल उन्नयन, नए उत्पादों के विकास और खरीदारों को चिह्नित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

अधिक जानकारी के लिए कृपया mas@eximbankindia.in पर लिखें।

एक्ज़िम बैंक का मार्केट आउटरीच कार्यक्रम

एक्ज़िम बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर केंद्रित अपना पहला मार्केट आउटरीच कार्यक्रम (ई-मॉप) म्यांमार और कंबोडिया में लॉन्च किया। ई-मॉप भारतीय उद्यमों के लिए वेल्यू एडिशन और उभरते बाजारों के उभरते क्षेत्रों में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए की गई एक पहल है।

स्वास्थ्य सेवा को म्यांमार और कंबोडिया सरकारों ने प्राथमिक क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। म्यांमार के लोग विदेशों में इलाज के लिए भारी रकम (लगभग 60 लाख यूएस डॉलर) खर्च करते हैं। हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट, यूरोलॉजी आदि के अस्पतालों की देश में भारी मांग है। हालांकि, पिछले एक दशक के दौरान सतत आर्थिक वृद्धि के चलते कंबोडिया ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। तथापि, देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। कुल मिलाकर देश में आबादी और अस्पतालों के बेड का अनुपात 1000 की आबादी पर 0.71 बेड का है और इसमें भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्थिति है। मैग्नेटिक रेजोनैंस इमेजिंग (एमआरआई) या कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैनर आदि जैसे अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता बहुत सीमित है।

इस क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए, एक्ज़िम बैंक के नेतृत्व में मल्टी स्पेशलिटी और सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों, मेडिकल उपकरणों तथा डिवाइस विनिर्माताओं और पैथोलॉजी लैब तथा जांच केंद्रों के सदस्यों वाला एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 5-7 फरवरी, 2018 तक म्यांमार और कंबोडिया के दौरे पर रहा। प्रतिनिधिमंडल ने इस आउटरीच कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों की सरकारों, चैंबरों, व्यापार संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के परामर्शदाताओं जैसे विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की।

यांगून, म्यांमार में उद्घाटन समारोह में डॉ. चॉ जिन थान, महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं खेल मंत्रालय, म्यांमार सरकार और प्रो. आंग तुन थेट, वरिष्ठ अर्थशास्त्री और म्यांमार के लिए शांति आयोग के सदस्य, ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं, नॉम पेन्ह, कंबोडिया में कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो. टान वोच छेंग, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्वास्थ्य मंत्रालय, कंबोडिया ने किया। इस अवसर पर सुश्री मणिका जैन, कंबोडिया में भारत की उच्चायुक्त भी उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय कंपनियों और म्यांमार तथा कंबोडिया की कंपनियों के बीच बिजनेस टू बिजनेस बैठकें आयोजित की गईं और स्थानीय अस्पतालों का दौरा भी किया गया।

इस अवसर पर डॉ. चॉ जिन थान ने कहा, ''हाल के वर्षों में म्यांमार सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने के बावजूद, इस क्षेत्र को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय कंपनियों के लिए केवल निवेश की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि म्यांमार से भारत में स्वास्थ्य पर्यटन के लिहाज से भी अच्छे अवसर हैं।''

प्रो. डॉ. आंग तुन थेट ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा, ''देश ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को हाल ही में प्राथमिक क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है और अन्य देशों के लिए निवेश के रास्ते खोले हैं। म्यांमार सरकार देश में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने की इच्छुक है।''

प्रो. टान वोच छेंग, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्वास्थ्य मंत्रालय, कंबोडिया ने कहा कि कंबोडिया निवेश के लिए वृद्धिशील रूप से पसंदीदा जगह बन रहा है और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सरकार के लिए भी प्राथमिकता रखता है।

इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश अवसरों का उल्लेख करते हुए श्री देबाशिस मल्लिक, उप प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक ने कहा, परिवर्तन के दौर से गुजरती अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए म्यांमार और कंबोडिया में स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय और प्रोफेशनलों के लिए अच्छे अवसर हैं। हालांकि म्यांमार और कंबोडिया के लोगों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति इस क्षेत्र के अन्य देशों के मुकाबले बहुत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य सेवा उपकरण, फार्मास्युटिकल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशिक्षण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें भारतीय कंपनियां म्यांमार और कंबोडिया में निवेश पर विचार कर सकती हैं। एक्ज़िम बैंक 'एक्ट ईस्ट' नीति के अंतर्गत परियोजना विकास निधि के जरिए सीएलएमवी क्षेत्र में भारतीय निजी क्षेत्र के निवेश को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को म्यांमार और कंबोडिया में संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

घाना

घाना पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक संगठन (इकोवास) का सदस्य है। घाना की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2017 में बढ़कर 7.9% हो गई, जो 2016 में 3.7% थी। इस वृद्धि का प्रमुख कारण त्वेनेबोआ-एन्येन्ना-टोम (टीईएन) से तेल एवं गैस उत्पादन का बढ़ना रहा। निकट भविष्य में जुबली तेल क्षेत्र से भी तेल उत्पादन बढ़ने की संभावना है। उधर, कोकोआ क्षेत्र में कीतमों और पेड़ों के भंडार की निम्न गुणवत्ता के कारण कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ, 2018 में बैंकिंग क्षेत्र के समेकन से वर्ष के अंत तक बैंकों की न्यूनतम पूंजी जरूरतें बढ़ने के चलते सेवा क्षेत्र में वृद्धि भी प्रभावित हो सकती है। परिणामतः 2018 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.6% तथा 2019 में घटकर 5.9% रहने के आसार हैं।

वार्षिक उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति दोबारा बैंक ऑफ घाना के मध्यावधि लक्ष्य 8% से 2% अधिक या कम के आसपास रहने के आसार हैं, जिसमें पिछले पांच साल के मुकाबले सख्त मौद्रिक नीति परिलक्षित होती है। मुद्रास्फीति जो 2017 में औसतन 12.4% रही, उसके 2018 और 2019 में घटते हुए क्रमशः 10.5% और 9.1% रहने के आसार हैं। घाना की मुद्रा सेडी में वस्तु निर्यातों पर निर्भरता और उभरते बाजारों के प्रति निवेशकों के बदलते रुझान को देखते हुए अस्थिरता की आशंका है। तेल उत्पादन और आयात की मांग बढ़ने तथा बेहतर रेमिटैंस के चलते 2018-22 के दौरान चालू खाता घाटा जीडीपी का 3.9 प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना है।

स्पेन

2017 में स्पेन की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2016 की 3.3 प्रतिशत से घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई। इसकी मुख्य वजह रही साल की अंतिम तिमाही का कैटेलन संकट। हालांकि, इस अंतिम तिमाही में लेबर मार्केट इंडिकेटर कुछ नरम रहा, लेकिन हाई-फ्रीक्वेंसी आर्थिक इंडिकेटर तुलनात्मक रूप से मजबूत रहे। फिर भी बहुत मुमकिन है कि निवेशकों के रुझान और वृद्धि के पहलुओं को देखते हुए स्थिति पुनः तनावग्रस्त हो जाए। इसकी संभावना अधिक है कि कैटेलोनिया में तुलनात्मक स्थिरता आए और इस क्षेत्र की वृद्धि दर पर बहुत ज्यादा असर न पड़े। फिर भी 2018 में वास्तवित जीडीपी वृद्धि दर 2.7% रहने की संभावना है। 2014-16 के दौरान तीन साल की मुद्रा अवस्फीति स्थिति के बाद तेल कीमतों में गिरावट के चलते 2017 में यूरोपीय संघ में मुद्रास्फीति औसतन 2% बनी रही। इसमें 2017 की पहली तिमाही में मुख्य रूप से तेल कीमतों के आधार प्रभाव और उच्चतर खाद्य कीमतें परिलक्षित होती हैं। तथापि, मूल मुद्रास्फीति (ऊर्जा और अप्रसंस्कृत खाद्य को छोड़कर) मध्यम ही रही। 2018 के आधार प्रभावों और घरेलू मांग कम होने के कारण 2018-19 में मुद्रास्फीति के 1.5% रहने के आसार हैं। 2017 में चालू खाता जीडीपी का 1.5% सरप्लस रहा। इस अच्छे प्रदर्शन का मुख्य कारण वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोत्तरी रहा, जिसके चलते व्यापार घाटा कम हुआ और सेवा क्षेत्र में भी मजबूती दर्ज की गई। लेकिन बढ़ती तेल कीमतों के चलते निर्यात वृद्धि अधिक होने से 2018 में चालू खाता सरप्लस घटकर 1.3% रहने का पूर्वानुमान है, जिससे आयात बिल रेज करने में मदद मिलेगी।

थाईलैंड

थाईलैंड की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2016 की 3.3% से बढ़कर 2017 में 3.7% हो गई। इसका मुख्य कारण निजी खपत और एशियाई देशों से मांग में सुधार आना रहा। आसियान देशों में बढ़ती संभावनाओं के चलते आगामी वर्षों में निर्यात वृद्धि बढ़ने की उम्मीद है। वैश्विक वस्तु कीमतों में सुधार और घरेलू मांग बढ़ने से भी मुद्रास्फीति दबाव धीरे-धीरे बढ़ा है, जिससे उपभोक्ता मूल्य 2016 के 0.2% से बढ़कर 2017 में 0.7% हो गए। हालांकि 2018 में मुद्रा विनिमय दर में गिरावट आने और वैश्विक वस्तु कीमतों में बढ़ोत्तरी के चलते उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 2018 में 1.6% रहने की संभावना है। 2018 में थाई बात भी अन्य एशियाई मुद्राओं की तरह कर कटौतियों और यूएस में दरों के बढ़ने से प्रभावित होगी, जिसका असर बाजार में निवेशकों के भरोसे पर भी पड़ेगा। 2017 के दौरान चालू खाता सरप्लस जीडीपी का 11.6% रहा। हालांकि यह सरप्लस कम होने के संकेत मिलते हैं और 2018-22 के दौरान यह घटकर जीडीपी का 10.9% हो जाने की संभावना है। इसकी वजह है- वैश्विक वस्तु कीमतों के बढ़ने से मर्चेंडाइज आयात और निर्यात में अच्छी वृद्धि तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश में तेजी आने से आयातों में वृद्धि।

कजाकिस्तान

कजाकिस्तान की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2016 की तुलना में 0.9% बढ़कर 2017 में 4% रही। इसका कारण कशगान तेल क्षेत्र से तेल उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन रहा। 2017 में उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 2016 के 14.2% से घटकर 7.4% रही, जो नेशनल बैंक ऑफ कजाकिस्तान के लक्ष्य के अनुरूप है। मुद्रास्फीति कम रहने की मुख्य वजह मुद्रा मूल्यवृद्धि रही, जिससे आयातित मुद्रास्फीति कम करने में मदद मिली। 2018 में बाहरी मुद्रास्फीति दबाव (वैश्विक खाद्य एवं गैर-तेल वस्तुओं की कीमतें) कम रहने की संभावना है और मुद्रास्फीति कम होकर 6.5% के स्तर पर आ सकती है। कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे में होने वाले उतार-चढ़ाव तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव की ओर संकेत करते हैं। 2017 में तेंगे यूएस डॉलर के मुकाबले औसतन 4.9% मजबूत हुआ और इसकी कीमत 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 326 तेंगे रही। इसकी वजह तेल कीमतों में आया सुधार, बढ़ता निर्यात और सकारात्मक वास्तविक ब्याज दरें रही। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति में सख्ती अपनाने की उम्मीदों के चलते 2018 में तेंगे के मूल्य में कुछ गिरावट आने की आशंका है। बढ़ते तेल निर्यात और उच्च तेल कीमतों के चलते 2017 में चालू खाता घटकर जीडीपी का 3.1% हो गया। 2018 में तेल कीमतें अधिक रहने की संभावना है और चालू खाता घाटा घटकर जीडीपी का 0.4% हो जाएगा।

मलेशियाई रिंगित

फरवरी में मलेशियाई रिंगित लंदन क्लोजिंग दरों पर यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 3.8975 से 3.9150 पर आ गया। बैंक नेगारा मलेशिया (बीएनएम) ने 7 मार्च की अपनी मौद्रिक नीति की बैठक में बेंचमार्क ओवरनाइट पॉलिसी रेट को 3.25% रखा, क्योंकि बैंक ने 25 जनवरी को ही इसमें 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोत्तरी की थी। यूएस दरों के तेजी से बढ़ने के चलते वैश्विक इक्विटी की बढ़ती बाजार उम्मीदों के कारण मलेशियाई रिंगित के मूल्य में बीते तीन महीनों में पहली बार मासिक गिरावट देखी गई। इससे इक्विटी में 0.3 अरब यूएस डॉलर की बिकवाली हुई, जो नवंबर 2016 के बाद से सबसे बड़ी जावक है। यह उल्लेखनीय है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगातार छठी बार बढ़ी और वर्ष की अंतिम तिमाही में वर्ष दर वर्ष 5.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि तीसरी तिमाही में यह वर्ष दर वर्ष वृद्धि 6.2% थी। वार्षिक वृद्धि दर 5.9% रही, जो 2014 के बाद से सबसे अधिक है। वर्ष की शुरुआत में आम चुनाव से पहले सरकारी खर्च में संभावित बढ़ोतरी आर्थिक वृद्धि को रफ्तार दे सकती है, जिसके आगे भी मजबूत बने रहने की संभावना है। खबरों को आधार बनाकर देखा जाए तो इसके संकेत बढ़ रहे हैं कि सरकार आम चुनावों की तैयारी कर रही है। लेकिन पिछले चुनावों के विपरीत, अबकी बार चुनावों के बाद वित्तीय बाजारों पर चुनावी नतीजों का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी वजह वोटरों का बड़ी संख्या में बाहर निकलना और वोट करना, बीएन के सबसे अधिक सीटें जीतने की संभावना है। रिंगित को इस साल चालू खाते के विस्तार और यूएस दोहरे घाटे के बढ़ने से डॉलर के कमजोर होने की संभावना जैसे फैक्टरों से भी मजबूती मिलेगी। अंतिम तिमाही का चालू खाता 12.9 अरब मलेशियाई रिंगित रहा, जो 2014 की दूसरी तिमाही के बाद सबसे अधिक है और चालू खाता सरप्लस 2016 के 29.0 अरब मलेशियाई रिंगित से बढ़कर 2017 में 40.3 अरब मलेशियाई रिंगित हो गया। चालू खाता ऊर्जा निर्यात और पर्यटन में नेट वृद्धि के कारण और बढ़ने की उम्मीद है।

फिलीपीन पेसो

फरवरी के दौरान फिलीपीन पेसो लंदन क्लोजिंग दरों पर यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 52.147 से 49.830 पर आ गया। फिलीपींस के सेंट्रल बैंक बीएसपी ने 8 फरवरी की अपनी मौद्रिक नीति की बैठक में बेंचमार्क ओवरनाइट रिवर्स रेपो रेट को 3.0% रखा। बीएसपी ने 15 फरवरी को घोषणा की थी कि 2 मार्च से आरआरआर में एक प्रतिशत की कटौती कर इसे 19.0% किया जाएगा। फिलीपीन पेसो वैश्विक इक्विटी, व्यापार घाटा बढ़ने की खबर और बीएसपी द्वारा आरआरआर को एक प्रतिशत कम किए जाने के चलते फरवरी के दौरान डॉलर के मुकाबले दोबारा गिरा। हालांकि महीने के अंत तक पेसो कुछ संभला और बीएसपी गवर्नर एस्पेनिला के अनुसार यह सबसे खराब प्रदर्शन वाली एशिया एक्स-जापान मुद्रा रही और बढ़ते व्यापार घाटे के चलते इसमें और गिरावट आने की आशंका है। दिसंबर का रिकार्ड व्यापार घाटा नवंबर के 3.8 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 4.0 अरब यूएस डॉलर हो गया, जो विशेष रूप से दिसंबर में पहला कर सुधार पैकेज मंजूर होने और पिछले महीने लागू होने के बाद 2018 की परिघटनाओं का संकेत है। जनवरी में समग्र भुगतान संतुलन में 531 मिलियन यूएस डॉलर का घाटा दर्ज किया गया, जिससे पेसो के संभलने की कोई उम्मीद नहीं है। फरवरी में आई एस्पेनिला की टिप्पणी में इस वर्ष अपेक्षित समय से पहले ही एक और दर बढ़ोत्तरी का जोखिम भी बताया गया है। बेंचमार्क ओवरनाइट रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने के अलावा एस्पेनिला ने कहा, बीएसपी सावधि जमा सुविधा (टीडीएफ) दरों को बढ़ाकर या घटाकर नीलामी वॉल्यूम में परिवर्तन करते हुए पॉलिसी रेट को सख्त कर सकता है। नोट करें कि मार्च में होने वाली टीडीएफ नीलामी में थोड़ी भी बढ़ोत्तरी आरआरआर में कटौती करने के कारण लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए होगी।

सिंगापुर डॉलर

फरवरी के दौरान सिंगापुर डॉलर लंदन क्लोजिंग दरों पर यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 1.3100 से 1.3232 पर आ गया। मलेशियाई रिंगित के मुकाबले सिंगापुर डॉलर 2.9752 से गिरकर 2.9587 पर आ गया। वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता के चलते फरवरी में सिंगापुर डॉलर में नवंबर 2016 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि निवेशक फेड दरों के तेजी से बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे। फरवरी में बाजार में बिकवाली के दौरान सिंगापुर डॉलर की नॉमिनल विनमय दर जनवरी के मिडपॉइंट से औसत 0.7% के मुकाबले मिडपॉइंट से 0.1% नीचे रही, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। निवेशकों को निकट भविष्य में इसमें और गिरावट आने की आशंका है, विशेष रूप से तब, जब यदि फेड ने और आक्रामक रुख अपना लिया। हालांकि, अमेरिका में अन्य फैक्टरों के साथ-साथ ट्विन डेफिसिट की समस्या के बढ़ने और यूएस डॉलर के कमजोर होने से सिंगापुर डॉलर के कुछ मजबूत होकर उभरने की संभवना है। इसके अतिरिक्त, निवेशकों को यह भी लगता है कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर 2021-2025 के बीच जीएसटी के 7% से 9% रहने के बावजूद (एमएएस) इस साल अपनी मौद्रिक नीति को थोड़ा सख्त बनाएगी। ऐसी उम्मीद मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव के कारण है। मूल मुद्रास्फीति के रुझानों पर गौर किया जाना चाहिए, जिसके 2.0% के आसपास बने रहने की उम्मीद है। मूल मुद्रास्फीति दिसंबर में वर्ष-दर-वर्ष 3.3% से बढ़कर जनवरी में वर्ष-दर-वर्ष 1.4% रही। सिंगापुर की मूल मुद्रास्फीति का असर आवास तथा निजी सड़क परिवहन लागत पर पड़ता है। इसलिए उच्च मूल मुद्रास्फीति की मुख्य वजहें उपयोग में आने वाली वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की कीमतें होंगी। साल की पहली तिमाही में बिजली की टैरिफ दरें पहले ही 6.2% के उच्च स्तर पर रहीं और जुलाई में पानी की कीमतें बढ़ना भी तय माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी दरें बढ़ने से पहले रेस्टोरेंट आदि की सेवाएं महंगी होने की भी संभावना है।

संकेतक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	
जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर, बिलियन यूएस डॉलर)	1874.3	1863.6	1919.4	2043.3	2147.2	2271.0[e]	2585.0[f]	
***	1502.7	1475.5	1501.2	1579.2	1640.3	1714.2	1929.0[f]	
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (यू एस डॉलर)	6.7	5.5	6.4	7.5	8.0	7.1[re]	6.7[re]	
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	5.0	1.5	5.6	-0.2	0.7	4.9[re]	3.4[re]	
उद्योग	7.8	3.3	3.8	7.5	8.8	5.6[re]	5.5[re]	
सेवाएँ	6.6	8.3	7.7	9.7	9.7	7.7[re]	7.9[re]	
जीडीपी में क्षेत्रगत हिस्सा (%)								
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	18.5	18.2	18.6	18.0	17.5	17.4[re]	17.1[re]	
उद्योग	32.5	31.8	30.8	30.2	29.6	28.8[re]	29.1[re]	
सेवाएँ	49.0	50.0	50.6	51.8	52.9	53.8[re]	53.8[re]	
जनसंख्या (मिलियन में)	1247.5	1263.6	1278.6	1293.9	1309.1	1324.8	1340.1[f]	
मुद्रास्फीति दर (सीपीआई, वार्षिक औसत %)	8.3	10.2	9.5	5.9	4.9	3.8	4.87	(मई'18)
मुद्रास्फीति दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	8.9	7.4	6.0	2.0	-2.5	1.7	4.43	(मई'18)
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5[e]	3.5[e]	
विनिमय दर (₹ / यूएस डॉलर, औसत)	47.9	54.4	60.5	61.1	65.5	67.1	68.02	(जून 18,'18)
विनिमय दर (₹ / यूरो, औसत)	65.9	70.1	81.2	77.5	72.3	73.6	78.85	(जून 18,'18)
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	306	300.4	314.4	310.3	262.3	276.5	303.3	
%परिवर्तन	22.5	-1.8	4.7	-1.3	-15.5	5.4	9.9^	
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	56.7	60.9	63.2	56.7	30.6	31.6	37.4	
%परिवर्तन	55.9	7.3	3.8	-10.2	-46.1	3.4	18.5^	
गैर- तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	249.2	239.5	251.2	253.6	231.7	244.9	265.9	
%परिवर्तन	16.8	-3.9	4.9	0.9	-8.6	5.7	8.7^	
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	489.3	490.7	450.2	448	381	382.7	464.7	
%परिवर्तन	32.3	0.3	-8.3	-0.5	-15	0.5	20.9^	
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	155	164	164.8	138.3	82.9	86.9	108.6	
%परिवर्तन	46.2	5.9	0.4	-16	-40	4.7	24.9^	
गैर- तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	334.3	326.7	285.4	309.7	298.1	295.9	356.1	
%परिवर्तन	26.7	-2.3	-12.6	8.5	-3.8	-0.7	19.7^	
व्यापार शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	-183.3	-190.3	-135.8	-137.7	-118.7	-106.2	-161.4	
सेवा निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	140.9	145.7	151.8	158.1	154.3	163.1	195.1	
सॉफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	62.2	65.9	69.4	73.1	74.2	73.7	72.2	
सेवा आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	76.9	80.8	78.7	81.6	84.6	95.7	117.5	
सेवा संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)	64	64.9	73.1	76.5	69.7	67.4	77.6	
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	-78.2	-87.8	-32.4	-26.8	-22.1	-14.4	-48.7	
डीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष (%)	-4.2	-4.8	-1.7	-1.3	-1.1	-0.6	-1.9	
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	294.4	292	304.2	341.6	360.2	370	413.1	(जून 08,'18)
विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	360.8	409.4	446.2	474.7	485	471.9	513.4	(दिसं.'17)
जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण अनुपात (%)	20.5	22.3	23.9	23.2	23.4	20.2	20.3	(जून'17)
अल्पावधि ऋण (यूएस बिलियन डॉलर)	78.2	96.7	91.7	85.5	83.4	88	97.6	(दिसं.'17)
अल्पावधि ऋण / कुल ऋण (%)	21.7	23.6	20.5	18	17.2	18.6	19.0	(दिसं.'17)
कुल ऋण चुकौती अनुपात (%)	6	5.9	5.9	7.6	8.8	8.3	6.3	(जून'17)
एफ़डीआई (बिलियन यूएस डॉलर)	46.6	34.3	36	45.1	55.6	60	62.0	
जीडीआर/एडीआर (बिलियन यूएस डॉलर)	0.6	0.2	0.02	1.3	0.4	-	-	
एफ़आईआई (नेट) (बिलियन यूएस डॉलर)	16.8	27.6	5	40.9	-4	7.7	22.2	
एफ़डीआई जावक (बिलियन यूएस डॉलर)	10.9	7.1	9.2	4	8.9	7	9.3	

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक; केंद्रीय बजट, आरबीआई मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट और साप्ताहिक सांख्यिकी सप्लीमेंट, वित्त मंत्रालय; सीएसओ; ईआईयू; नैसकॉम; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ़) डब्ल्यूओ; आईएमएफ।

नोट: e-भारत सरकार के अनुमान; re- संशोधित आकलन, ae- अग्रिम अनुमान; f-आई आई एफ पूर्वानुमान; - उपलब्ध नहीं; - ^-% गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन;

9 जून, 2018 को अपडेट

व्यापार और भागीदारी अवसर

भारत से निर्यातों के लिए व्यापार अवसर

पल्पिंग मशीनरी

कागज और लुगदी उद्योग के लिए कृषि आधारित अवशिष्ट से स्वच्छ लुगदी और एनर्जी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स का डिजाइन और विनिर्माण करने वाली एक कंपनी, जो फाइबर तैयार करने वाला सिस्टम, वेट वाशिंग सिस्टम, कंटिन्युअस डाइजेस्टर सिस्टम, केमिकल रिकवरी प्लांट और लाइम कैल्सिनर जैसे उत्पाद बनाती है।

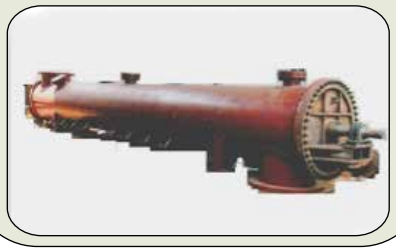

पुर्जे

ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टरों की पुर्जों की निर्माता; यह कंपनी निर्यात उन्मुख इकाइयों को ट्रकों और ट्रेलरों के लिए इंजीनियरिंग पुर्जों की आपूर्ति करती है। भारत और अमेरिका में परिचालनरत यह कंपनी दुनिया के कई देशों को विभिन्न इंजीनियरिंग पुर्जों की आपूर्ति करती है।

वस्त्र एवं कपड़ा

हिमाचल प्रदेश स्थित हथकरघा इकाई, जो ऊनी फैब्रिक और वस्त्रों का उत्पादन करती है। इस सहकारी संस्था ने समूचे घाटी क्षेत्र से करीब 200 बुनकरों को निर्यात गुणवत्ता वाले हथकरघा वस्त्रों और घर की सजावट के सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया है।

स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और प्रशिक्षण

अग्रणी स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और प्रशिक्षण कंपनी, जो प्रौद्योगिकी नवोन्मेष तथा शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराती है। इनमें करियर संबंधी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

नॉन–लेदर हैंडबैग

महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा स्टार्ट–अप वाटरप्रूफ बैग, वॉलेट और यात्राओं में काम आने वाले छोटे–मोटे सामान (ट्रैवल असेसरीज) बना रहा है। यह स्टार्ट अप पेटा द्वारा प्रमाणित है, जो प्राकृतिक कॉर्क फैब्रिक का इस्तेमाल कर अपने उत्पाद बनाता है।

औद्योगिक और सुरक्षा वर्दी

विभिन्न औद्योगिक कार्यों के लिए वर्दी के डिजाइन बनाने और वर्दी का उत्पादन करने वाली कंपनी। कंपनी आग से सुरक्षा करने वाले परिधान बनाती है, जिनमें पूरा शरीर ढकने वाली वर्दी, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट और इनरवेयर आदि शामिल हैं।

भागीदारी अवसर

परियोजनाओं में अवसर

(I) बांग्लादेश में एक सरकारी कंपनी ने 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के डिजाइन, आपूर्ति और टर्नकी आधार पर उसकी स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय टेंडर के जरिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

(II) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी ने आइवरी कोस्ट में कार्यालय भवनों, वेयरहाउस, होटलों, शॉपिंग मॉल, अम्यूज़मेंट पार्क, अंतरराष्ट्रीय मेडिकल क्लीनिक, शैक्षिक संस्थाओं, आवासीय क्षेत्र और खेल सुविधाओं के निर्माण तथा प्रबंधन के लिए पार्टनरों के चयन हेतु रुचि प्रकटन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

निर्यात अवसर

(I) मिस्र की एप्लायंस बनाने वाली एक कंपनी भारत से कोल्ड रोल्ड कॉइल का आयात करना चाहती है। कंपनी को 100 एमटी डीसी01 स्टील ग्रेड की जरूरत है।

(II) पोलैंड के एक आयातक ने भारत से बासमती चावल और मिश्रित मसाले आयात करने में रुचि दिखाई है। खेप पोलैंड के ग्दानिया बंदरगाह पहुंचानी होगी।

इच्छुक पार्टियां इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं समूह से संपर्क कर सकती हैं:

संपर्क सूत्र: फोन: 022–2217 2600, एक्सटेंशन: 2830/2707/2737, फैक्स: 022–2218 8268; ईमेल: mas@eximbankindia.in